जिसमें चना और रेंचा का फसल संबंधी प्रदर्शन बिलकुल असफल रहा और गेहूं की फसल को उत्पादन दर भी कम होने की संभावना है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गेहू और मक्का जैसी फसलों की किस्म जिन्हें एक समय श्री नारमन बोरलाग द्वारा विकसित कि ा गया था, की तरह की चना की एक भी किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा अभी तक विकसित नहीं की जा सकी है; और

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसधान संस्थान किसी स्थायी योजना के तहत गंगादियारा का आधिग्रहण करने और इस क्षेत्र का विकास करने के लिए सतत प्रयास करने का विचार रखता है और यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली (भा०कृ०अ० स०) ने बोचानी गांव (जम लपुर ब्लाक), मुंगेर जिले में चना (बी जी–261, बी जी 256 तथा बी जी–241) तथा (पूसा बारानी) सहित रबी फसलों पर क्षेत्र प्रदर्शन के आस-पास क्षेत्र दिवस का आयोजन किया था । किसानों की आम फसलों की तुलना में चने तथा रेंचा पर प्रदर्शन बहुत अच्छी दशाओं में किया गया था । गेहूं प्रदर्शन से फसल की उतनी ही अच्छी फसल मिलने की भी आशा की जाती है । गेहू प्रदर्शन के परिणामों का अभी इन्तजार है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमन् देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुसंधान संस्थानों तथा कृषि विश्व-विद्यालयों द्वारा चने की अधिक उपज देने वाली किस्में विकसित की गई है।

(ग) जी नहीं, श्रीमन्, किसानों तथा राज्य कृषि विभागों के विस्तार कार्यकर्त्ताओं के लिए नवीनतम कृषि, प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के उद्देश्य से अल्प अवधि लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की किसानों तक प्रौद्योगिकी का प्रसार करने वाली प्रायोजनाए केवल प्रथम स्तर के प्रदर्शनों को आयोजित करती हैं। गगा दियारा के विकास के लिए लम्बी अवधि की प्रायोजनाओं को चलाने का दायित्व बिहार सरकार का है।

अरहर की फसल

2170. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी संस्थान द्वारा हाल ही में अरहर की ऐसी कोई किस्म विकसित की है जिसे एक वर्ष में तीन बार काटा जा सकता है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि उपयोग किये गये बन्द गोभी के पौधों को सब्जी के प्रयोजनार्थ पुनः उगाया जा सकता है और इसी तरह गाजर-मूली की मुन्डी को काट कर उपयोग के लिए पुनः व उगाया जा सकता है ;

(ग) यदि हां, तो इस तरीके को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नये प्रयोगों के लिए किसानों को प्रोत्साहित नहीं करती है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (इक्रीसेट) द्वारा अरहर की जल्दी पकने वाली किस्मों में से एक किस्म आई सी पी एल–87 (प्रगति) विकसित की गई है जो खरीफ मौसम में पहले की ही तरह उगाई जाती है परन्तु इसका रखरखाव पूरे वर्ष किया जाता है और इसकी वर्ष में दो से तीन बार फसल ली जाती है। तथापि इस पद्धति की संभाव्यता की पुष्टिकारक जांचे की जा रही हैं।

(ख) और (ग) उपयोग में लाये गये अथवा काटे गये बंदगोभी के पौधों को आमतौर पर पुनः नहीं उगाया जाता, परन्तु बिहार तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शीघ्र पकने वाली बंदगोभी की किस्मों में पौधों के शीर्ष को काटने के बाद उन्हे उसी स्थान में छोड़ दिया जाता है तथा उन्हें पेड़ी की फसल के लिए रखा जाता है। पेड़ी से उगाई गई फसल की क्वालिटी खराब होती है तथा इस पर एफिड का अधिक प्रकोप होता है। यह मिट्टी में मौजूद फसल के अन्य रोग कारकों के साथ मिलकर मिट्टी में रोग संक्रमण को प्रोत्साहित भी करता है।

ताजे काटे गये गाजर तथा मूली के ऊपरी हिस्से का रोपण बीज उत्पादन के लिए किया जाता है। बेहतर उपज तथा अच्छी क्वालिटी का बीज प्राप्त करने के लिए कटे हुए भाग के आकार को मानकीकृत करने के लिए अनुसंधान किया गया है।

(घ) यह सच नहीं है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किसानों को नये परीक्षणों के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। बल्कि दूसरी तरफ परिषद् किसानों को प्रोत्साहित भी करती है, यदि उनकी उपलब्धियों का कोई व्यावहारिक महत्व है। इस संबंध में लैन्टाना बग के नियन्त्रण विधि के विकास के लिए एक किसान को पुरस्कार देने का उदाहरण दिया जा सकता है।

Allotment of land to cooperative group housing societies

2171. SHRI KAILASH PATI MISHRA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that different pockets of land are available with the DDA which have been earmarked for allotment to Cooperative Group Housing Societies;

(b) if so, what are the names of the areas and the Price fixed therefor;

(c) whether it is also a fact that the Cooperative Group Housing Societies formed in 1983 are likely to be allotted land only in the Palam group of colonies in South West Delhi; and

(d) if so, by when the land is likely to be allotted to these Cooperative Group Housing Societies and at what rate?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) Land is mainly earmarked in Palam area in South-West Delhi for allotment to co-operative group housing societies.

(d) All steps are being taken to allot the earmarked land in South-West Delhi to the co-operative societies as early as possible Formalities are being completed and applications would be invited in very near future from the societies for allotment of land through advertisements in press. The provisional rate worked out by the DDA for the land to be allotted in this area is Rs. 474 per sq. metre.

Steel plant units under expansion

2172. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) what is the number of public sector steel plant units which are under expansion and are yet to be commissioned;

(b) whether there are any units which have already been commissioned but are lying idle or are working below their utilisation capacity; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF ENERGY AND THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI VASANT SATHE): (a) The following three plants of SAIL are being expanded at present:—

(1) Bhilai Steel Plant from 2.5 MT ingot steel capacity to 4 MT capacity.

(2) Bokaro Steel Plant from 1.7 MT ingot steel capacity to 4 MT capacity.